THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) and (b) The Governing body of the colleges are empowered for sanctioning leave to the teachers as well as to run day to day administration of respective colleges. The Delhi University had informed that the Delhi University Students Union (DUSU) communicated the names of teachers who have not completed their courses in some colleges. The University is in the process of forwarding the names of such teachers to the respective colleges for appropriate action.

Award to Magician P.C. Sarkar

1958. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the magician P.C. Sarkar Junior has recently been conferred, Merlin Award, a recognition for the greatest magician in the world, given by the International Magician Society;

(b) whether Government had ever given any ward to the great magician and his father, P.C. Sarkar (Sr.), as a recognition for their achievement; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (c) Government is not associated with the conferment of Merlin award to the Magicians. However, Shri Pratul Chandra Sor-car (Senior), Magician, born in 1913 in West Bengal was awarded Padma Shri in the year 1964 in the field of Arts.

Changes in the text books of Uttar Pradesh

1959. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be. pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain school text books in Uttar Pradesh have undergone changes where those killed during the course of destruction of Babri Masjid on December 6, 1992; have been described as MARTYRS: and

(b) if so, the details thereof and the response of Government thereto?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) U.P. Government has informed that Text Books approved by their Department of Basic and Secondary Education do not contain any such reference.

(b) Does not arise.

Setting up of Self Financing Autonomous Colleges

1960. SHRI P. PRABHAKAR RED DY: Will the Minister of HUMAN RE SOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that sometime back, a special task force was constituted by the Human Resource Development (HRD) Ministry to examine, inter alia, the question of setting up high quality and self financing autonomous colleges and Institutes, which could be authorised to award their own degrees;

(b) if so, whether the Task Force has since submitted its report to Government; and

(c) if so, the major recommendations thereof and by when a decision is likely to be taken in the matter?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (c) No Special Task Force was constituted by the Government to examine, among other things, the question of setting up of a high quality and self-finnacing autonomous colleges and institutions which could be authorised to award their own degrees. However, a Task Force constituted to examine the amendments proposed by the UGC in the UGC Act, has recently submitted its report. The Task Force, inter alia, has suggested amendments in the UGC Act so that Central Government may make rules for institutions and or universities, colleges, whether self-financing or otherwise so that they could also have right to confer degrees.

स्कूलों में कृषि शिक्षा

1961. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सच है कि सरकार सभी स्कूलों में पांचवी कक्षा के बाद कृषि शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या जैव-कृषि (ऑरर्गेनिक फार्मिंग) जैसे नए विषयों को उसमें शामिल किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा0 मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी नही।

(ख) प्रश्न नही उठता।

महिला समृद्धि योजना

1962. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या योजना आयोग ने महिला समृद्धि योजना को जारी न रखने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नही, तो सरकार द्वारा महिला समृद्धि योजना को सफल बनाने हेतु क्या-क्या कदम उठाये जा रहे है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) से (ग) चूंकि महिला समृद्धि योजना को कार्यान्वित करने की परिचालन लागत बहुत अधिक थी, इसलिए योजना आयोग ने इस स्कीम के मूल्यांकन पर विचार करने तथा विभाग से विचार-विमर्श करने के पश्चात इस स्कीम को इन्दिरा महिला स्कीम में मिला देने की सलाह दी है। संशोधित स्कीम का प्रारूप सरकार के विचाराधीन है।

प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर व्यय

1963. **श्री राजमोहिन्दर सिंह** :

श्री कपिल सिब्बल :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सच है कि देश में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चो के लिए प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 40,000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि नही, तो इस संबंध में सरकार का प्राकलन क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा के मद पर कुल 20,000 करोड़ रुपये मात्र, व्यय किये जाने का प्रस्ताव किया गया है, यदि नही, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा0 मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) शिक्षा विभाग ने 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी प्रस्ताव के अन्तर्निहित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए तत्कालीन मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री मुही राम सैकिया की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति का गठन किया था। समिति ने स्कूली शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्य तौर पर पांच वर्षो की अवधि के लिए 40,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान किया था।

(ग) शिक्षा विभाग के लिए नौवीं योजना (1996-2002) का परिव्यय 20,381.00 करोड़ रुपये है।